E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन में बैंको का योगदान

मोना यादव
शोधार्थी
विषयः अर्थशास्त्र

डॉ. पवन कुमार श्रीवास्तव,
मार्गदर्शक,
श्रीमंत माधवराव सिंधिया
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शिवपुरी (म.प्र.)

Paper Received date
05/06/2026
Publishing Date
10/06/2026
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.21443318

शोध सार

गुना एवं अशोकनगर को गांवों की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पंत के अनुसार भारत माता ग्राम वासिनी है। गुना एवं अषोकनगर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण संस्कृति और अर्थव्यवस्था की प्रधानता बनी हुई है। दोनों जिलों की लगभग 03 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और दोनों जिलों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। सन् 1951 में ग्रामीण जनसंख्या 1 लाख 35 हजार थी स्पष्ट है, देश में ग्रामीण जनसंख्या का गुना एवं अशोकनगर अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

जनसंख्या का विस्तार गांव एवं शहर दोनों में तीव्र गति से हुआ है, लेकिन गांव की अपेक्षा शहर की आबादी में अधिक वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक प्रजननता होने के बावजूद शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होना गांवों से लोगों का शहरों की ओर पलायन का परिणाम है। इस प्रकार जन समस्याएँ और अधिक जटिल होती जा रही हैं।

मुख्य बिन्दुः संस्कृति, जनसंख्या, आबादी, प्रजननता, पलायन, समस्याएं

IMPACT FACTOR 5.924

गुना एवं अशोकनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक विज्ञान उतना आवश्यक नहीं समझा गया है, जितना कि अन्य प्रगतिशील मध्य प्रदेश के अन्य जिले के लोगों ने इसे अपने जीवन में ग्रहण किया है। सदियों तक गुना एवं अषोकनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान के उपयोग का सम्बन्ध नहीं था। आज भी गुना एवं अशोकनगर के अनेक गांव ऐसे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं।

इन समस्याओं से निपटने के लिए विगत अनेक वर्षों से मध्य प्रदेष के सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। गुना एवं अषोकनगर के ग्राम्य जीवन में भूख, गरीबी, नियमित रोजगार का अभाव, खेती सम्बन्धी समस्याएं, अशिक्षा अज्ञानता, समुचित विकास कार्यक्रमों का अभाव जैसी अनेक ज्वलन्त समस्याएं विद्यमान हैं। गुना एवं अषोकनगर के अलग–अलग गाँव से किसानों के द्वारा आत्महत्याएँ की जा रही है, इसकी खबरें समय–समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। मनरेगा के द्वारा गुना एवं अशोकनगर की ग्रामीण स्थिति को काफी बल मिला है, जिसके द्वारा समावेशी विकास

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। गुना एवं अषोकनगर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों द्वारा काफी सुधारात्मक कार्य किये जा रहे है, जिससे लोगों की स्थिति बदले और परिवारों का आर्थिक अर्थिक सषक्तिकरण हो सके।

गुना एवं अषोकनगर जिले में दो तरह की बैंक सरकारी एवं प्राइवेट बैंक है। इन बैंकों क द्वारा लोगो को विभिन्न कार्यो के लिये अलग –अलग प्रकार के ऋण दिये जाते है, जिससे लोगो की आवष्यताओं की पूर्ति हो सके। सरकारी एवं प्राइवेट बैंको की ब्याज दर भी अलग– अलग हैं, षिक्षित एवं सरकारी कर्मचारी अधिकतर सरकारी बैंको से ऋण लेते हैं, जिससे वे लाभान्वित हो सकें। अषिक्षित एवं किसान वर्ग सहकारी, प्राइवेट एवं सरकारी बैंको से भी ऋण लेते हैं।

राष्ट्रीय और निजी बैंकों की सूची	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**निजी क्षेत्र के बैंक**
1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	1. एक्सिस बैंक
2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	2. एचडीएफसी बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)	3. आईसीआईसीआई बैंक
4. बैंक ऑफ इंडिया (BOI)	
5. यूको बैंक	
6. केनरा बैंक	
7. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI)	
8. मध्यांचल ग्रामीण बैंक	

प्रो. किनले के अनुसार, ''बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है जिन्हें उसकी आवष्यकता है तथा जिसके पास जनता द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है।''[1]

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में बैंक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है– ''बैंकिंग कम्पनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती है।'' और ''बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है, जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चैक, ड्राफ्ट, आदेष अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके।''

गुना एवं अशोकनगर जिले में आजादी के पष्चात बहुत तेजी से बैंको का बिस्तार हुआ जिससे लोग सूदखोर एवं साहूकारों से मुक्ति पा सकें। दोंनो जिलों में किसान वर्ग विभिन्न प्रकार के ऋण लेता है, जिससे वह अपने कृशि कार्यो का विकास कर सकें। वर्तमान में विभिन्न बैंको के द्वारा कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिससे कृशक वर्ग अधिक सषकत बन सके।

गुना और अशोकनगर जिले की बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, और मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

ये बैंक इन योजनाओं के तहत बेटियों के खाते खोलने, आर्थिक सहायता प्रदान करने और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने जैसे कार्य करती हैं।

सुकन्या समृद्धि योजनाः यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। बैंक बेटियों के लिए खाते खोलकर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी व्यक्तिगत सहयोग दिया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध लोगों को आजीवन आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजनाः इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु सहायता और दिव्यांगता सहायता जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बहुत से गरीब एवं कमजोर कृशक वर्ग के लोगो का राहत मिल रही है।

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का उद्देष्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बैंकिग का विस्तार कर देषी बैंकरों तथा महाजनों के स्थान पर संस्थागत वित्त का विस्तार करना था। भारतीय स्टेट बैंक की सफलता को देखते हुए 19 जुलाई, सन् 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं 15 अप्रैल, 1980 को 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके फलस्वरूप देष का लगभग 90 प्रतिषत बैंकिंग व्यवसाय राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास आ गया। तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2 अक्टूबर सन् 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण विकास के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास हो सके।''[2]

समय के साथ सतत् परिवर्तन एवं विकास विश्व के समस्त देशों के लिए एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। किसी भी देष की बैंकों की कार्यप्रणाली का प्रभाव उस देश में कार्य करने वाली उन सभी बैंकिंग संस्थाओं पर पड़ता है, जो किसी–न–किसी रुप में विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे– कृषि, व्यापार, उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह–निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। समय के अनुसार विकास भी जरुरी है व विकास के साथ–साथ औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर प्रगति होना भी जरुरी है। व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए वित्तीय सहायता की आवष्यकता पड़ती है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज समाज एवं उद्योग की वित्तीय आवष्यकताओं में जो भी परिवर्तन एवं संवर्द्धन हो रहा है उसमें बैंकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही बैंकों की कार्यप्रणाली सरल एवं स्पष्ट हो व बैंकों की नीतियां पारदर्षी हो तो विकास को और गति दिया जा सकता है।''[3]

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण बैंकिंग संस्थाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जोकि पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये संस्थान एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न वर्गों को उनकी आवष्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह एक विस्तृत, जटिल एवं मजबूत संगठन है, जो कि देष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें संगठित एवं असंगठित निजी एवं सार्वजनिक, देसी एवं विदेषी, ग्रामीण एवं शहरी, आधुनिक एवं परम्परागत सभी प्रकार के रुप देखने को मिलते हैं। वास्तव में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था यहाँ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की की भांति अपनी विविधताओं से परिपूर्ण है।''[4]

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरूआत 2 अक्टूबर सन् 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेष में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पष्चिम बंगाल में माल्दा में इन बैंक की स्थापना की गई, बाद में देष के अन्य क्षेत्रों में भी इन बैंक का विस्तार किया गया। दिसम्बर

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

1975, को देष में केवल 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। दिसम्बर 1980, को देष में 85 शाखायें कार्यरत् थी। 1985, में 188 शाखायें, 31 मार्च 1990 को 196, 31 मार्च सन् 2004, को 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, 500 जिलों के अन्तर्गत 14,507 शाखाएं कार्य कर रही थी, जिनमें से 82.6 प्रतिषत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ये ग्रामीण साख में 37 प्रतिशत का योगदान देती है। क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक के विलय प्रक्रिया का प्रारम्भ 31 अगस्त सन् 2006, तक 134 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलाकर 42 नए बैंक गठित किए गए थे। 31 मार्च 2011 को 82, 31 मार्च 2013 को 64, 31 मार्च 2014 को 56, मार्च 2019 को 45 एवं 1 अप्रैल 2020 को घटकर कुल 43 शाखायें रह गई हैं। वर्तमान 31 मार्च 2021 में इन बैंक को 16 राज्यों में 18 बैंक ने प्रायोजित किया है। अब इनकी संख्या 45 से घटकर कुल 43 हो गई, विलय की प्रक्रिया अभी जारी है।''[5]

ग्रामीण बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्ग जिनमें लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगार व कलाकार शामिल हैं, को ऋण सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे कृषक वर्ग कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादकता को बड़ा सके। भूमिहीन मजदूर अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सके। साथ ही ग्रामीण कारीगार तथा कलाकार अपनी कार्यकुषलता को और बड़ा सके व ग्रामीण स्वरोजगार को जीवित रख सके। वर्तमान ग्रामीण जन को साहूकारी के सिकंजे से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाया। इसीलिए भी ग्रामीण जनो को साहूकारों के सिकंजे से मुक्ति दिलाने, वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की लागत को कम करने, स्थानीय कार्य दषाओं के अनुरूप स्थानीय वर्ग से कार्य लेने तथा ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय समस्याओं का उपयुक्त एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने एवं भारतीय अर्थशास्त्र की शोषण रहित सामाजीकरण की प्रक्रिया में गतिषीलता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की भूमिका एक मित्र, एक मार्गदर्षक तथा हितैषी के रूप में महसूस की गई।''[6]

भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण से भी ग्रामीण साख समस्या गंभीर ही बनी रही। फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों को भी वर्ष 1966 में कृषि एवं ग्रामीण जनो के सहयोग के लिए दिशा–निर्देश प्रदान किये गये। इन बैंकों ने भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग करना प्रारम्भ किया।

गुना एवं अशोकनगर जिलों में बैंक की शुरूआत[7]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 3 के अधीन म.प्र. के प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण 20 जनवरी 1976 को होशंगाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थाना की गई। इसका प्रवर्तन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया है। जो देश में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सातवाँ बैंक है। इस प्रकार म.प्र. में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद से प्रारम्भ होकर गतिशील हो गया। जिसका कृत्रिम व्यक्ति के रूप में प्रथम वैधानिक अस्तित्व है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होषंगाबाद को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का स्थान प्राप्त है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में है। गुना एवं अशोकनगर जिलों में सरकारी एवं गैरसरकारी बैंकों की स्थिति अलग–अलग है, इसका कारण गुना अषोकनगर जिले से अलग हुआ है। वर्तमान में गुना जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी जिले की संख्या 39 है, जिसमें से 11 बैंक मनरेगा की योजनाओं को अनुदानित करते हैं जो निम्न हैं– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, नावार्ड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, सहकारी बैंक, मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक, ऑरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई सी आई सी आई बैंक ये सभी प्रमुख बैंक है जो सभी मनरेगा योजनाओं को संचालित करने में अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। इसी क्रम में अशोकनगर जिले में 9 बैंक मनरेगा की योजनाओं को अनुदानित करती हैं, जो निम्न हैं– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नावार्ड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

सहकारी बैंक, मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई सी आई सी आई बैंक हैं। इन दोंनो जिलो में बैंको के द्वारा मनरेगा योजना को अधिक सषक्त बनाया है। बैंके स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज एवं विभिन्न केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना को अधिक सषक्त बनाने में बैकों की विषेश भूमिका है। वर्तमान में 1 अप्रैल 2019 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 39 जिलों में मध्यप्रदेश गामीण बैंक का नेटवर्क फैल हुआ है। वर्तमान में इसका प्रमुख कार्यालय इन्दौर में स्थित है।

संदर्भ सूची

1. प्रो.वी. पी. अग्रवाल एवं सुधीर कुमार शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेषन्स :आगरा, बैंकिंग एवं बीमा, पृष्ठ संख्या –2 सन् 2018
2. धनकर – बैंकिंग एवं वित्तीय सामान्य सचेतता, धनकड़ पब्लिकेषन्स प्रा. लि. मेरठ, यू.पी. सन् 2019, पृष्ठ सख्या–51
3. डॉ. टी.एन. माथुर, डॉ. ममता जैन, डॉ. दिनेश त्रिपाठी – भारतीय बैंकिंग प्रणाली, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2018, पृ.सं.–2
4. प्रो.वी. पी. अग्रवाल एवं सुधीर कुमार शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स :आगरा, बैंकिंग एवं बीमा, पृष्ठ संख्या –2 सन् 2018
5. राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक संस्थागत विकास विभाग मुंबई वर्ष 31 मार्च 2021 पृष्ठ संख्या 176
6. डॉ. टी.एन. माथुर, डॉ. ममता जैन डॉ. दिनेश त्रिपाठी – भारतीय बैंकिंग प्रणाली, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2018, पृ.सं.–139,140
7. मुख्य शाखा इन्दौर एवं सेन्ट्रल मध्ध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा होषंगाबाद वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च 2020–2021 पृष्ठ संख्या 20